315 अमीनों की वाणिज्य कर विभाग में भर्ती जल्द

20 जिलों में नियमित व 55 जिलों में सीजनल अमीन होंगे नियुक्त

अपर उजाला ब्यूरो

लखनऊ।

वाणिज्यकर विभाग में जल्द ही 315 अमीनों की भर्ती होगी। इनमें से 150 नियमित अमीन प्रदेश के 20 बड़े जिलों में और शेष 55 जिलों में 165 सीजनल अमीन भर्ती किए जाएंगे।

आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किसानों के एक लाख रुपये तक के कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। इसके तहत राज्य सरकार ने हाल में करीब 85 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। इसके लिए सरकार ने अपने संसाधनों से करीब 36 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी। इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। इसे कम करने के लिए सरकार का फोकस अब राजस्व वसूली पर है। चूंकि वाणिज्य कर विभाग सर्वाधिक राजस्व देता है। लिहाजा इस विभाग पर वसूली का भी सर्वाधिक दबाव है।

इसके मद्देनजर पिछले दिनों वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में राजस्व वसूली बढ़ाने पर चर्चा हुई थी। इसमें विभागीय अधिकारियों ने यह मुद्दा उठाया था कि जब तक अमीनों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, तब तक राजस्व वसूली की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। इस पर अपर मुख्य सचिव अरके तिवारी ने विभाग के रिक्त अमीनों के रिक्त पदों पर भर्ती का निर्देश दिया था। साथ ही कहा था कि जिन जिलों में नियमित अमीन के पद नहीं है, वहां सीजनल अमीन नियुक्त करने का भी प्रस्ताव तैयार कराया जाए। इस आधार पर विभाग अब इन दोनों श्रेणियों में अमीनों की भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसे एक-दो दिन में अंतिम रूप देकर अगले सप्ताह तक शासन को भेज दिया जाएगा।

नियमित अमीन के 150 पद खाली : वाणिज्य कर विभाग में नियमित अमीनों के कुल 475 पद हैं। इनमें से करीब 150 पद रिक्त हैं। इन्हीं पदों पर भर्ती होनी है। हालांकि ये सभी पद महज 20 बड़े जिलों के लिए ही स्वीकृत हैं। जबकि 55 जिलों में वसूली का काम सीजनल अमीनों के जरिये कराया जाता है। एक जिले में औसतन तीन सीजनल अमीन रखे जाते हैं। इसीलिए करीब 165 सीजनल अमीनों की भी भर्ती करने का प्रस्ताव तैयार हो रहा है।

अगले सप्ताह तक शासन को भेज दिया जाएगा प्रस्ताव

विभाग के एक उच्चाधिकारी के मुताबिक सभी जोनल अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव मंगाने का काम एक-दो दिन में पूरा हो जाएगा। इसको मुख्यालय स्तर पर परीक्षण होगा। इसके बाद सभी जोन के प्रस्तावों को मिलाकर एक समग्र प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। संभावना है कि अगले सप्ताह तक प्रस्ताव को शासन को भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्व वसूली के दबाव को देखते हुए उम्मीद है कि नवंबर में अमीनों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

नवंबर में शुरू हो सकती है भर्ती प्रक्रिया

विभाग के एक उच्चाधिकारी के मुताबिक सभी जोनल अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव मंगाने का काम एक-दो दिन में पूरा हो जाएगा। इसको मुख्यालय स्तर पर परीक्षण होगा। इसके बाद सभी जोन के प्रस्तावों को मिलाकर एक समग्र प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। संभावना है कि अगले सप्ताह तक प्रस्ताव को शासन को भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्व वसूली के दबाव को देखते हुए उम्मीद है कि नवंबर में अमीनों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।